

nt>

Title: Need to increase the funds under MPLAD Scheme.

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : अध्यक्ष जी, कुछ महीने पहले माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एम.पी.लेड्स की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हम एम.पी.जे. से पूछा गया था कि (व्यवधान)

MR. SPEAKER: If time has not been utilised for other things, we would have covered many more Members.

श्रीमती रंजीत रंजन : कुछ डिमांड्स रखी गई थीं कि आखिर एम.पी.जे. की अपने क्षेत्र के लिए क्या डिमांड्स हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको हम कल पूरे समय यहां बिठाएंगे।

श्रीमती रंजीत रंजन : उसमें हम लोगों ने कुछ मांगें रखी थीं, जिसमें हम लोगों ने फंड को बढ़ाने की डिमांड रखी थी। क्योंकि एक विधायक को जो फंड मिलता है, वह प्रति विधान सभा एक करोड़ रुपये है जबकि एम.पी.जे. के क्षेत्र में कहीं छः विधानसभा, कहीं नौ विधान सभा या कहीं-कहीं तो 17 विधान सभा क्षेत्र भी हैं। हम लोगों ने उस समय यह डिमांड रखी थी कि कम से कम इसे विधान सभा क्षेत्र वाइज एक करोड़ रुपये किया जाये। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो इस फंड को पांच या छः करोड़ करने की डिमांड भी हमने रखी थी। (व्यवधान) मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : हम सब लोगों की यही डिमांड है कि इस फंड को बढ़ाया जाये, नहीं तो इसे खत्म किया जाये। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are only interrupting here. She is also advocating your cause. You are only interrupting her.

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैक्सिमम एम.पी.जे., जैसा आप देख रहे हैं, उनकी डिमांड थी कि आप इस फंड को बंद कर दीजिए या फिर इसे बढ़ा दीजिए क्योंकि हर एम.पी. से लोगों की बहुत एक्सपेक्टेडेशन होती है। उनके मन में भ्रम होता है कि आप सैंटर से जुड़े हुए हैं इसलिए आप जो चाहते हैं, वह करा सकते हैं।

मेरा दूसरी एक महत्वपूर्ण डिमांड थी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, वह कोसी क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र की आधी आबादी कोसी नदी और आधी गंगा नदी से पीड़ित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है, वह ठीक है। आपने बहुत पापुलर मुद्दा उठाया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन : वहां पर मैक्सिमम पुल हैं। हम यह डिमांड रखते हैं कि 40 से 50 लाख रुपये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे विषय पर नहीं बोल सकतीं।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन : मैं वही मुद्दा कह रही हूँ। हमारी डिमांड यह थी कि एक योजना में हमें 40 से 50 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी जाये जबकि एमपीलेड फंड में इतना प्रावधान नहीं है। उसमें अभी तक केवल 20 से 25 लाख रुपये ही खर्च किये जा सकते हैं। मेरे ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब हमें नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि इस फंड को या तो खत्म कर दिया जाये या इसे बढ़ाया जाये। धन्यवाद।